

1

प्रेषक,

ओम प्रसादा,
ग्रन्थालय,
चत्तृपाटन जिला।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिहार, उधमसिंहनगर, शार्दूल, नैनीताल,
विधौरागढ़, टिहरी गढ़वाल एवं देहरादून।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 30 नवम्बर, 2012

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों हेतु राज्य आपदा मोद्दन निधि मद से तृतीय किस्त के रूप में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का भित्तेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों हेतु जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों के सापेक्ष उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सम्यक विचारोपरान्त तृतीय किस्त के रूप में संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार कुल ₹ 40.00 करोड़ (₹ छालीस करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2— उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के शासनादेश संख्या-32-7/2011-NDM-I, दिनांक 16 जनवरी, 2012 के माध्यम से राज्य आपदा मोद्दन निधि से धनराशि स्वीकृत/व्यय किये जाने सम्बन्धी मानक पुनरीक्षित कर दिये गये हैं। जिसकी प्रति आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है, का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

3. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से हुई क्षति में राज्य आपदा मोद्दन निधि (SDRF) से व्यय हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या-10 में भारत सरकार द्वारा विभागवार तात्कालिक प्रकृति के कार्य स्पष्ट किये गये हैं तथा तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यों में मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। अतः प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यों यथा—मार्गों एवं पुलों, पेयजल आपूर्ति से संबंधित अवसरचनायें (हेण्ड पम्प, कुंरे, टैंक, क्षतिग्रस्त पाइप लाइन इत्यादि), विद्युत (केवल ऐसे क्षेत्रों जहाँ तात्कालिक रूप से विद्युत व्यवस्था की जानी होगी), प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, पंधायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु धनराशि व्यय की जायेगी तथा 'निर्धारित अवधि' में ही मरम्मत कार्य पूर्ण किये जायेंगे।

4. आहरण व व्यव केवल उन मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यों के लिए किया जायेगा, जो एस.डी.आर.एफ. के दिशा निर्देशों में अनुमन्य हैं एवं जिनके लिए राज्य स्तरीय समिति से नियमानुसार आवश्यकता का आंकलन करा लिया गया हो और व्यय आंकलन के अनुसार ही किया जायेगा।

5. मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों हेतु उक्त स्वीकृत धनराशि में से ₹ 1.00 करोड़ की धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग के तकनीकी शास्त्रिकारियों (सम्म सर) से तकनीकी परीक्षणोपरान्त द्वी पहान की जायेगी। जामनातेज

h

प्रक्रम्य: -2

संख्या-795, दिनांक 30.08.2012 द्वारा जिलाधिकारियों के वित्तीय स्वीकृति अधिकार ₹ 25.00 लाख से बढ़ाकर ₹ 1.00 करोड़ किये गये है। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2012-13 में मानसून अवधि के दौरान क्षतिग्रस्त सार्वजनिक एवं विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों हेतु ही लागू होगी।

6. स्वीकृत धनराशि में से 10% धनराशि पेयजल आपूर्ति से संबंधित परिसम्पत्तियों (यथा—हैण्ड पम्प, कुर्हे, टैंक, क्षतिग्रस्त पाइपों इत्यादि) की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों में गाइड लाईन्स के अनुसार व्यय की जायेगी।

7. मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के साथ आहरित की जायेगी—

1. आगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग के अधिकारी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।

2. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें ताकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुये एवं सोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

3. कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिकारी अभियन्ता स्तर के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं। स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।

4. कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आगणन/मानधिक गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय। जिन आगणनों में स्तिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व प्राप्त पुस्तिका से रिकार्ड मेजरमेंट इंगित अदृश्य कराये जाय तथा इसका सत्यापन अधिकारी अभियन्ता स्वयं करें।

5. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिलाधिकारी एवं निर्माण इकाई का होगा।

6. स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त है तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों से आच्छादित है। स्वीकृत धनराशि नव निर्माण कार्यों में कदापि व्यय नहीं की जायेगी तथा गत वर्ष की योजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृत न की जाय।

7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवश्य धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा धनराशि निर्माण संस्था/विभाग को तब ही अवमुक्त की जायेगी, जब इस बात की लिखित रूप में पुष्ट हो जायें।

8. वास्तविक क्षति के कार्यों पर ही धनराशि स्वीकृत की जायेगी। सामान्य मरम्मत के कार्य प्राकृतिक आपदा की परिधि में नहीं आते हैं। अतः सामान्य मरम्मत के कार्यों, नव निर्माण तथा विकास कार्यों में धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

9. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में जांच कर धनराशि के दुरुपयोग व

अभियन्त्रित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध प्रथम दण्ड के रूप में बसूली, चित्तीय दण्ड के रूप में बसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ.आई.आर. (F.I.R.) की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10. क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों एवं हल्का बाहन मार्गों के प्रस्तावों पर वास्तविक क्षति के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी। प्रस्तावित मार्ग की कुल लम्बाई एवं क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई अनुसार लो०निं०विं० द्वारा प्रति कि०मी० सड़क निर्माण हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु कुल आगणन के अनुसार धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

11. अश्व मार्ग जन सामान्य के उपयोग में सर्वथा सुलभ नहीं होते हैं। अतः अश्वमार्गों के प्रस्ताव पर राज्य आपदा मोर्चन निधि से स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि अश्व मार्गों का उपयोग पैदल मार्ग के रूप में जन सामान्य द्वारा उपयोग होता है तो इस स्थिति में आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

12. पैदल मार्गों के प्रस्तावों में वास्तविक क्षति के अनुरूप ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी। मार्ग की कुल लम्बाई, क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई तथा मार्ग की मरम्मत कहाँ से कहाँ तक होनी है, यह स्पष्ट किया जाय। लो०निं०विं० द्वारा प्रति कि०मी० सड़क मरम्मत हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु अन्य आगणन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के जिला धनराशि, विकास खण्ड एवं स्थानीय निकाय आदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्राप्त आगणनों, जहाँ अधिशासी अभियन्ता स्तर के अभियन्ता न हो, वहाँ लो०निं०विं० के अधिशासी अभियन्ता से प्रमाणित/सत्यापित कर, वरें प्रतिहस्ताक्षरित करायी जाए।

14. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के संबंध में उप जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोर्चन निधि के ब्यय हेतु निर्धारित नवीन मद एवं मानकों से आच्छादित होने एवं निर्धारित समयावधि के अन्दर क्षति होने की पुष्टि तथा प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर सुस्पष्ट संस्तुति के बाद ही कार्य योजना सक्षम स्तर से स्वीकृत की जायेगी।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित जिलाधिकारी/ निर्माण एजेन्सी/ संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे और लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमत्य नहीं होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टेंडर आदि विषयक नियमों का अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

17. कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो ली जायेगी। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। तदनुसार ही कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर राज्य आपदा मोर्चन निधि से निर्मित कार्ययोजना का नाम, लागत, दिनांक तथा मद का नाम सीमेन्ट कॉर्नरीट पर अंकित कर दिया जाय।

18. भारत सरकार द्वारा नामित एक स्वतंत्र एजेन्सी से भी जनपदों के कार्यों का निरीक्षण व मूल्यांकन किया जायेगा। अतः जनपद स्तर पर कार्यों में निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित की जायेगी, जिसके द्वारा कार्य की क्षति, धनराशि के सही उपयोग गुणवत्ता आदि की समीक्षा की जायेगी।

19. जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय व्यवस्था के साथ प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपयोगिता प्रमाण पत्र द्वासान को प्रेषित किया जायेगा।

20. वित्तीय वर्ष 2012-13 तक राज्य आपदा मोर्चन निधि से जारी समस्त स्वीकृतियों तथा इसके सापेक्ष व्यय/समर्पित धनराशि का लेखा मिलान संबंधित जिलाधिकारी द्वारा महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहसादून में निश्चित रूप से प्रत्येक तीन माह में सुनिश्चित कराया जायेगा।

21. उपसेक्षत निर्देशानुसार धनराशि स्थीकृत की जायेगी। सज्ज आमदान मोबाइल निधि के ब्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों/प्रक्रिया का अनुपालन न होने पर संबंधित जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं कार्यदाती संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

22. स्थीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2013 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्थीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

23. उक्त पर होने वाला ब्यय थालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-ब्ययक अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)-आयोजनेत्तर-800-अन्य ब्यय-00-13-आपदा राहत निधि से ब्यय-42-अन्य ब्यय के नामे डाला जायेगा।

24. यह आदेश वित्त विभाग के अ. शा. संख्या-120 NP/XXVII-5/2012, दिनांक 27 नवम्बर, 2012 द्वारा प्राप्त उमकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीन,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या- 669(1)/XVIII-(2)/12-4 (7) / 2012 TC एवं तारिखांक:

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओरेशराय बिलिंग, नाजरा, देहरादून।
- 2— प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3— आयुवक्त, गढ़वाल भण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ भण्डल, मैनीताल।
- 4— अपर सचिव, वित्त एवं ब्याय अनुभाग।
- 5— कोषाधिकारी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, बागेश्वर, मैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल एवं देहरादून।
- 6— निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
- 7— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 8— राज्य सूचना अधिकारी, एनोआईसी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9— प्रभारी अधिकारी, भीड़िया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10—बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
- 11—वित्त अनुभाग-5
- 12—धर्म आष्टांग संघसभी चत्वारिंशी।
- 13—मार्ग फाइल।

आशा से,


(संलग्न वडोनी)
अनु सचिव

क्र.सं.	जामघह का नाम	स्थीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)
1	छत्तीरकोशी	10.00
2	झद्गप्रयाग	8.00
3	हरिहार	5.00
4	झधमसिंहनगर	8.00
5	बागेश्वर	3.00
6	नैनीताल	2.00
7	पिथौरागढ़	2.00
8	टिहरी गढ़वाल	1.00
9	देहरादून	1.00
	कुल योग	40.00

(कुल र जालीम करोड़ रुपय)

26/10/2012
(संतोष पल्लोनी)
अनु संधिष्ठ